खेती से लाभ

2861. **श्री राम पूजन पटेल :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि किसानों के पारिश्रमिक और खेती पर होने वाले अन्य व्यय को जोड़ा जाये तो खेती एक घाटे का व्यवसाय है ;

(ख) यदि हां, तो किसानों के आर्थिक सुधार हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) कितने प्रतिशत किसान गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। कृषि मूल्य आयोग जिन्सों के न्यूनतम समर्थन । अधिप्राप्ति मूल्यों की सिफारिश करते समय अन्य बातों के साथ-साथ कृषि फसलों से उत्पादन की लागत के बारे में भी विचार करता है । किसानों को लाभ-प्रद मूल्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये समर्थन। अधिप्राप्ति मूल्यों का इस ढंग से निर्धारित किया जाता है ताकि उत्पादन-लागत पर समुचित मार्जिन सुलभ हो सके । प्रमुख फसलों की उत्पादन-लागत का अनुमान लगाने संबंधी विस्तृत योजना के अन्तर्गत फसलों की उत्पादन लागत में सभी प्रकार के नकद तथा अन्य रूप से होने वाले खर्चों, जिसमें निजी आदानों जैसे पारिवारिक श्रम का आकलित मूल्य, निजी पूंजी निवेश पर ब्याज और निजी भूमि के किराये का आकलित मूल्य भी शामिल है , को हिसाब में लिया जाता है ।

(ख) सरकार किसानों की आर्थिक दशा में सुधार करने के लिये फार्म उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि करने और आदान संसाधनों के इष्टतम आवंटन के माध्यम से उत्पादन लागत को कम करने के लिये सतत कदम उठा रही है । उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना, रासायनिक उर्वरकों का अपेक्षाकृत ज्यादा इस्तेमाल करना, अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का विस्तार करना, वनस्पति रक्षण के उपाय करना, पैकेज प्रणालियों को अपनाना, मिनीकटों का वितरण करना, सामुदायिक नर्सरियां लगाना, दलहनों रिज्योबियम- कल्चर का इस्तेमाल करना, बारानी खेती के लिये आदानों और प्रौद्योगिकी का विकास और प्रचार प्रसार करना, और ठीक समय पर पर्याप्त बिजली और डीजल की सप्लाई करना । किसानों के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिये विपणन और मूल्य संबंधी समर्थन सुलभ कराया जाता है ।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाली लगभग 51 प्रतिशत आबादी है, लेकिन विशेष रूप से किसानों के बारे में ऐसी प्रतिशता सुलभ नहीं है ।

Sheep Development Council

2862. SHRI BHAGATRAM MANHAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to State:

(a). whether it is a fact that the meeting of Sheep Development Council was held in New Delhi this year;

(b) if so, what is the number of officials and non-officials who participated in the meeting;

(c) whether the payment of TA|DA to these officials and non-officials has not been made in spite of complaints; and

(d) if so, what are the reasons for the delay in expediting the payment of TAjDA to officials and non-officials who attended this meeting and by which date the payments will be made to them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R.V. SWAMINATHAN): (a) Yes, Sir.

(b) 19 Members including officials and non-officials attended the meeting.

(c) and (d) Officers who attended the meeting would draw their TA|DA from source where their salaries are drawn. Three non-official members were paid T.A. advance equivalent to to and fro-first class Railway fare from the place of commencement of their journey. Final payment of TA|DA in respect of these members after adjustment against advance has since been released.

Operation flood I and II and CLUSA Oilseeds Products in Gujarat

2863. SHRI ABDUL REHMAN SHEIKH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what was the expenditure and layout approved by Government on Operation Flood I and II and CLUSA Oilseeds Projects and the actual release so far; and

(b) whether the large scale deviations in releases were approved in advance by Government if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R.V. SWAMINATHAN): (a) and (b) The original statewise allocation of Operation Flood-I for Rs. 95.4 crores was revised to Rs. 116.4 crores. Because of the slow offtake of funds by the States, the state-wise ceiling was later abolished on recommendation of joint FAO-WFP-CCI Mission that reviewed the project during September, 1979. Details of state-wise, original allocation, sanctioned [1] amount and utilisation of the funds by the states are indicated below:

State	Original allocation	Total sanctioned Plan	Utilisation by the States
1. Andhra Pradesh	2.46	7.229	5.041
2. Bihar	3.99	3.849	3.236
3. Delhi	5.08	1.563	9.034
4. Gujarat	8.94	25.326	21.862
5. Haryana	3.82	5.07	3.742
6. Maharashtra	17.25	25.768	18.050
7. Punjab	3.82	5.454	5.286
8. Rajasthan	3.82	4.976	3.997
9. Tamil Nadu	8.87	18.584	14.27
10. Uttar Pradesh	3.82	7.963	5.765
11. West Bengal	18.92	20.64	14.897
12. IDC's direct expenditure	14.61	11.585	11.37
TOTAL	95.40	138.007	116.550